

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2576
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना

†2576. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख औद्योगिक और संभारतंत्र गलियारों के परस्पर पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां टाउनशिप वाले ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है और इसके लिए कितना बजट आवंटन किया गया है;

(ग) क्या इन पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप में से किसी एक को पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 462.4 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के साथ गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और उच्च बजट की मांग के बावजूद, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों को कम सरकारी अनुदान को दर्शाते हुए संशोधित कर कम कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): जैसा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा की गई थी, केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रमुख औद्योगिक और संभारतंत्र गलियारों के आस-पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने के लिए राज्यों की सहायता करना है। चुनौती-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से पहल में भाग लेने वाले राज्यों के साथ, कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों, कौशल केंद्रों और आवासीय परिसरों की मेजबानी करने वाले नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों के माध्यम से एक समग्र उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना की गई है।

(घ): दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों और संविधियों और अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2014-15 में 5634.85 करोड़ रुपये से 3 गुना से अधिक बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025-26 में 16990.07 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का संबंध है, सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2014-15 में 463.04 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 880 करोड़ रुपये हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आगे जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सभी व्यय स्वीकृत बजटीय आवंटन के तहत और विश्वविद्यालय के उपलब्ध आंतरिक राजस्व सृजन (आईआरजी) के भीतर किए गए हैं।
